## TO RETURN SECTOR LAND TO THE FARMERS

***925. SHRI DEEPAK MANGLA, M.L.A.**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that Sector-12 has been developed by the Government in Palwal in the year 2011 but further development has not been made in the said sector so far; and

b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to release the land of above said sector and return it to the farmers by conducting the survey of the area again, together with the time by which the above said proposal is likely to be materialized?

## REPLY

## MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER HARYANA

a) Yes, Sir, Haryana Shehri Vikas Pradhikaran has developed and allotted plots in Sector-12, Palwal, except for a pocket of approximately 19.422 acres which was under litigation.

b) Development works stand completed in August 2013 on 117.968 acres land of the sector, excluding an area of 19.422 acres which was under litigation. 327 residential plots stand already allotted. There is no proposal under consideration of the Government to return the already developed and allotted sector to the land owners.

# किसानो को सैक्टर की भूमि वापिस करना

*925. **श्री दीपक मंगला, एम०एल०ए० :** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2011 में पलवल में सरकार द्वारा सैक्टर 12 विकसित किया गया है परन्तु उक्त सैक्टर में आगे विकास अब तक नहीं हुआ है, तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सैक्टर की जमीन को मुक्त करने तथा क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण करके इसे किसानों को वापिस करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

## उत्तर

**मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा ।**

(क) हाँ, श्रीमान् जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सैक्टर–12 पलवल का विकास व भूखंडो का आबंटन किया है, केवल 19.422 एकड़ विवादास्पद क्षेत्र को छोड़कर ।

(ख) 19.422 एकड़ क्षेत्र जो कि विवाद के अधीन था को छोड़कर, इस सैक्टर की 117.968 एकड़ भूमि पर अगस्त 2013 में विकास कार्य पूर्ण हो गए थे । 327 आवासीय भूखण्ड भी आबंटित हैं। पहले से ही विकसित और आबंटित सैक्टर की भूमि को भू–स्वामियों को वापिस करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।